सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–**cm-251**
**22/05/2018**

# महिलाओं के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता :– मुख्यमंत्री

पटना, 22 मई 2018 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज पश्चिम चम्पारण जिला के हरनाटांड़ स्थित बिनवलिया में भारतीय थारु कल्याण महासंघ के 40वें वार्षिक महाधिवेशन का दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन किया। स्थानीय नेताओं ने फूल माला एवं गुलदस्ता भेंटकर मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर स्कूली छात्राओं ने स्वागत गान गाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। भारतीय थारु कल्याण महासंघ के सचिव श्री राजकुमार महतो ने मुख्यमंत्री के स्वागत में अभिनंदन पढ़ा। मुख्यमंत्री के स्वागत में थारू जनजाति की महिलाओं द्वारा झमटा नृत्य भी प्रस्तुत किया गया।

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सबसे पहले भारतीय थारु कल्याण महासंघ के 40वें वार्षिक महाधिवेशन के मौके पर मौजूद थारू समाज के लोगों को अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि साल में एक बार बाल्मीकिनगर इलाके के इस वन क्षेत्र का भ्रमण करने हम जरूर आते हैं। मेरा मानना है कि बिहार का यह सबसे सुंदर स्थल है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2009 में विकास यात्रा की शुरुआत हमने पश्चिम चंपारण से की थी और जब भी कोई यात्रा हम प्रारंभ करते हैं तो उसकी शुरूआत चंपारण की इस धरती से ही करते हैं। उन्होंने कहा कि 19 जनवरी 2009 को सुबह में ही हमने कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर समेकित थरुहट विकास अभिकरण का गठन किया। हरनाटांड में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें हमें यह मालूम हुआ था कि थारू समाज के लोगों को आदिवासी का दर्जा मिलने की मांग उठती रही है। इसके लिए कई नेताओं ने प्रयास किया और हम लोगों के नेता जॉर्ज साहब ने भी इसके लिए काफी प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि जब हम रेल मंत्री थे तब आदिवासी कल्याण मंत्री से हमारी अक्सर मुलाकात हुआ करती थी और इस संबंध में उनसे बातें करके हमने थारू समाज को आदिवासी की श्रेणी में शामिल करवाया। उन्होंने कहा कि थरुहट विकास अभिकरण को वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2017–18 तक 97 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये, जिसमें 260 योजनाओं पर काम शुरू किया गया, जिसमें 239 योजनायें पूरी हो गयी है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 27 करोड़ 61 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है और आज तक 125 करोड़ रुपये विभिन्न विकास योजनाओं के लिए उपलब्ध कराया जा चुका है। विकास यात्रा पर जब हम आये थे, तब उस समय 5 अनुसूचित जनजातीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया था, जिसमें अब तक 4 का उद्घाटन भी हो चुका है। इसके लिए 59 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये। आवासीय विद्यालयों के अतिरिक्त छात्रावास निर्माण के लिए 17 करोड़ रुपये मुहैया कराये गये। उन्होंने कहा कि एकलव्य आवासीय मॉडल विद्यालय निर्माण जो केंद्र की योजना है, इसके लिए 35 करोड़ रुपये भी उपलब्ध कराये गये। केंद्र की योजना में इसकी क्षमता 400 सीट की है लेकिन हमलोगों ने इस तरह के विद्यालयों की क्षमता को 720 सीट तक करने का तय किया। 320 सीटों पर आने वाले खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण बढ़ाने की मांग होती रही है लेकिन जब वर्ष 2021 की जनगणना होगी, तब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनकी आबादी के अनुरूप ही आरक्षण का लाभ बढ़ सकेगा। यह राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा कि बगहा–2 जो प्रखंड है, उसे आप सिंधाव में चाहते हैं, इसके लिए जिला प्रशासन को निर्देश

दिया गया है और इस संबंध में जिलाधिकारी अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। उन्होंने कहा कि यहां डिग्री कॉलेज खोलने की मांग की गई है, जबकि राज्य के हर अनुमंडल में सरकारी कॉलेज की स्थापना की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नौरंगिया गोलीकांड ने मुझे काफी व्यथित किया है। गोलीकांड के मामले में मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि हमने सभी नियमों को शिथिल कर पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिलवाया। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक योग्यता के अभाव में आश्रितों को नियोजन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी लेकिन उस घटना को देखते हुए नियोजन के संबंध में निर्धारित नियमों को शिथिल कर सात आश्रित लोगों के नियोजन की व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि सड़क, पुल–पुलिया, बिजली जैसे हर बुनियादी ढांचे का विकास पूरे बिहार में किया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी टोलों तक बिजली पहुंचा दी गई है और इस साल के अंत तक जो भी इच्छुक परिवार होंगे उनके घरों तक बिजली पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शौचालय निर्माण की दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और इसके लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी मोतिहारी आए थे और हमने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि बापू की 150वीं जयंती के मौके पर पूरे तौर पर लोगों को खुले में शौच से मुक्ति दिला दें। उन्होंने कहा कि बिहार पहला राज्य है, जहां महिलाओं को पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण मुहैया कराया गया। स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया, जिससे महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ। साइकिल और पोशाक योजना से लड़कियों के मन में आगे बढ़ने का उत्साह कायम हुआ। उन्होंने कहा कि नारी सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर ही बिहार में शराबबंदी लागू की गई। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सचेत और सतर्क रहना होगा ताकि शराब छोड़कर लोग दूसरी नशीली पदार्थ का सेवन न करने लगें। उन्होंने कहा कि बाल विवाह और दहेज प्रथा के उन्मूलन को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, यह महिला सशक्तिकरण और समाज सुधार की दिशा में उठाया गया कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक सामाजिक कुरीतियों से लोगों को छुटकारा नहीं मिलेगा, तब तक विकास का लाभ पूरे तौर पर उनको नहीं मिलेगा। जनसभा में मौजूद लोगों से अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी से नशामुक्ति तक समाज को पहुंचाना है, इसके साथ–साथ बाल विवाह और दहेज प्रथा से मुक्त भी समाज बनाना है।

बिहार में लागू हुई मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका मकसद बाल विवाह को रोकना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 2 वर्ष की उम्र पूरा करने वाली बालिकाओं को राज्य सरकार की तरफ से 5,000 रुपये मुहैया कराया जायेगा, जिसमें लड़की पैदा होने के वक्त उसके माता–पिता के खाते में 2000 रुपये, एक साल बाद आधार से लिंक होने पर 1,000 रुपये और 2 वर्ष की अवधि तक पूर्ण टीकाकरण होने पर पुनः 2000 रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहले से चल रही पोशाक योजना की राशि में भी बढ़ोत्तरी की गयी है, जिसमें कक्षा एक एवं दो में पढ़ने वाली लड़कियों को 400 रूपये की जगह 600 रुपये, कक्षा 3 से 5 में पढ़ने वाली बालिकाओं को 500 के बजाय 700 रुपये, कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए 700 की जगह 1,000 रुपये और कक्षा 9 से 12वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को अब 1,000 की जगह 1,500 रूपये की राशि पोशाक के लिए प्रदान की जाएगी। किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 7वीं से 12वीं में पढ़ने वाली लड़कियों को सैनेटरी नैपकिन के लिए पहले जहाँ 150 रुपये सालाना लड़कियों को दिये जाते थे, अब उनकी जगह उन्हें 300 रुपये प्रदान किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि बाल विवाह पर लगाम लगाने के लिए इंटरमीडिएट पास करने वाली अविवाहित लड़कियों को 10,000 रूपये की राशि मुहैया कराने का राज्य सरकार ने फैसला लिया है, वहीं ग्रेजुएशन करने वाली लड़कियों को 25,000 रुपये मुहैया कराने का भी राज्य सरकार ने

निश्चय किया है, वह चाहे कुंवारी हो या विवाहित। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से लिंग अनुपात सुधरेगा, भ्रूण हत्या में कमी आएगी, बाल विवाह रुकेगा, साथ ही लड़कियां शिक्षित होंगी। उन्होंने कहा कि समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष की उम्र वाले आंगनबाड़ी में पढ़ रहे बच्चों को पोशाक हेतु मिलने वाली पोशाक राशि में भी बढ़ोत्तरी की गयी है। आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को अब पोशाक के लिए 250 की जगह 400 रुपये प्रदान किये जायेंगे। इस प्रकार एक लड़की के पैदा होने से ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी करने तक सरकार उसपर 54,100 रुपये खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि पुरुषों को बेटे की तरह बेटी पर भी ध्यान देना चाहिए और बीमार पड़ने पर उसका इलाज भी कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि लड़की पैदा होने पर लोग पीड़ा महसूस करते हैं, अब लड़की होने पर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि थारू समाज में पहले से ही महिलाओं का सशक्तिकरण है और यहां पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की उपस्थिति है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर राज्य सरकार द्वारा 50,000 रूपये दिये जायेंगे, जबकि संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्राओं को राज्य सरकार 1,00,000 रूपये की सहायता प्रदान करेगी ताकि वह आगे की तैयारी कर सकें। उन्होंने कहा कि दलितों के उत्थान के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी अब उसका लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में शांति सद्भाव और प्रेम का भाव हर हाल में कायम रहे, यही हमारी इच्छा है। उन्होंने कहा कि मिल–जुलकर और एकजुट होकर हम जब काम करेंगे, तभी बिहार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में कामयाब होगा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय छात्रावास में रहने वाले छात्रों को 1,000 रूपये अनुदान के तौर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही 15 किलो अनाज भी हर महीने उन्हें दिया जा रहा है, जिसमें 9 किलो चावल और 6 किलो गेहूं छात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा। अति पिछड़े समाज के लोगों के लिए भी यह स्कीम लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग हाशिए पर खड़े हैं, उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बगहा को जिला बनाने की मांग लगातार होती रही है लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं कि बिहार में जब और भी जिले बनेंगे, उस सूची में बगहा भी शामिल होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार समाज कल्याण और विकास के काम में लगातार प्रयत्नशील है।

गन्ना किसानों को आश्वस्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों का किसी प्रकार का बकाया नहीं रहे, यही हमारा उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार नहीं थी तो क्या हालत थी। कई चीनी मिल बंद हो गए थे और जो खुले थे उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाये गये। उन्होंने कहा कि एथेनॉल बनाने से चीनी मिलों की आमदनी बढ़ी है और बिजली उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। जनसभा में उपस्थित लोगों से अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप अपने सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों के समक्ष उसे रखें, वह हम तक पहुंच जाएगी, फिर उसका तत्काल समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोगों की आवाज सुनने की कोशिश करते हैं। चम्पारण के प्रति मेरे दिल में जो श्रद्धा का भाव है वह कभी समाप्त नहीं होगा।

जनसभा को गन्ना उद्योग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एवं बगहा जिले के प्रभारी मंत्री श्री फिरोज अहमद उर्फ खुर्शीद आलम, सांसद श्री सतीश चंद्र दुबे, विधायक श्री धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह ने भी संबोधित किया।

इस अवसर पर विधायक श्री विनय बिहारी, पूर्व सांसद श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो, पूर्व सांसद श्री कैलाश बैठा, भारतीय थारू कल्याण महासंघ के अध्यक्ष श्री दीप नारायण प्रसाद, मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चन्द्रा, तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त श्री नर्मदेश्वर लाल, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, जिलाधिकारी श्री नीलेश देवड़े, पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद कुमार गुप्ता सहित वरीय अधिकारीगण अन्य गणमान्य व्यक्ति, भारतीय थारू कल्याण महासंघ से जुड़े पदाधिकारीगण एवं काफी तादाद में आमलोग उपस्थित थे।

इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने बाल्मीकिनगर व्याघ्र आरक्ष के भ्रमण के क्रम में पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा बाल्मीकिनगर व्याघ्र आरक्ष अंतर्गत वन्य प्राणियों के अनुश्रवण हेतु हाथी शेड का लोकार्पण किया। इसके पश्चात बर्ड्स ऑफ उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नामक पुस्तिका और एक पृथ्वी, शिक्षा द्वारा प्रकृति संरक्षण नेतृत्व मार्गदर्शिका 2018 का विमोचन किया।

******